

- नागरिकता के प्रश्नों का निरिधारण करने के लिये भारत के निरिवाचन आयोग के पास संवैधानिक या वैधानिक अधिकार का अभाव है ।
- नागरिकता निरिधारित करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है ।

- लाल बाबू हुसैन बनाम नरिवाचन पंजीकरण अधिकारी (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा कभितदाता सूची में पहले से सूचीबद्ध व्यक्तियों से उनकी नागरकिता पुनः साबति करने के लयि नहीं कहा जा सकता ।

▪ **SIR से संबंधति चुनौतियाँ:**

- वशिष पुनरीकषण (SIR) के दशिा-नरिदेशों के अनुसार अब [?] होती है, जसिसे कई पात्र नागरकिों के बाहर होने की आशंका है ।
- जनप्रतनिधितिव अधनियिम, 1950 (RPA) के अनुसार, केवल वही व्यक्तकििसी नरिवाचन कषेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जो उस कषेत्र में [?] (ordinarily resident) हों ।
- जो प्रवासी काम या शकिषा के लयि स्थायी रूप से कसिी नए स्थान पर स्थानांतरति हो गए हैं, वे अपने [?] पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं ।
- हालाँकि, SIR प्रक्रयिा में नागरकिों पर ही अपने पात्र होने का पूरा प्रमाण देने की ज़मिमेदारी डाली गई है ।
- बहिर सरकार के एक सर्वेकषण के अनुसार, जहाँ 87% लोगों के पास आधार कार्ड है, वही केवल 14% के पास मैट्रकुलेशन प्रमाणपत्र तथा सरिफ 2% के पास पासपोर्ट है ।
- मान्य दस्तावेज़ों की सूची से आधार को बाहर करने का नरिणय [?] को असमान रूप से प्रभावति कर सकता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-voter-roll-revision-in-bihar>

